

विदेशी शोध छात्रों को वीजा से जुड़ी शर्तों से दूर रखने का प्रस्ताव

भारतीयों को एच1बी वीजा से छूट संबंधी बिल में लाभ



वाशिंगटन | एजेसी

अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में शनिवार को वहां पीएचडी करने वाले भारतीयों सहित अन्य विदेशी नागरिकों को एच1बी वीजा नियमों से छूट दिए जाने संबंधी विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक से सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलने की उम्मीद है।

सांसद एरिक पॉलसन और माइक क्विगले ने शोध में छूट संबंधी विधेयक स्टॉपिंग ट्रेड इन अमेरिका पीएचडी फॉर्म लीविंग द इकोनॉमी (स्टैपल) पेश किया। इस विधेयक के अनुसार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में पीएचडी करने वाले विदेशी नागरिकों पर अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड और एच1बी वीजा संबंधी शर्तें लागू नहीं होनी चाहिए। यह सीधे तौर पर हजारों भारतीय छात्रों के लिए फायदेमंद है, जो



ट्रंप ने लगाई थी सख्ती

गत माह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच1बी वीजा नियमों को काफी कड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि अमेरिका में बाहरी लोगों को नौकरी देने के बजाए कंपनियां अमेरिकियों को नौकरी दें।

अमेरिकी कंपनियों को जरूरत के हिसाब से मिलेगी दक्षता

सांसद एरिक पॉलसन ने कहा कि हमारे यहां हजारों जॉब खाली होने जा रही है। अब 'स्टैपल' एक्ट तय करेगा कि अमेरिकी कंपनियों को उनकी जरूरत के हिसाब से दक्षता मिल सके। इन पेशेवरों के डिप्लोमा के साथ ग्रीन कार्ड या (ए) वीजा को जोड़कर इनके नई खोज और आविष्कार के जरिये अमेरिका को लाभ पहुंचा सकते हैं।

अमेरिका में विभिन्न विषयों पर पीएचडी करते हैं। ये वीजा सालाना आधार पर जारी किए जाते हैं। विधेयक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका में लगातार वीजा नियमों को कड़ा किया जा रहा है।

होनहार लोग अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे : सांसद एरिक पॉलसन ने कहा, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि दुनियाभर के होनहार लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान दें सकेंगे। अगर

वे डिग्री लेने अमेरिका आएंगे तो हम उन छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जो भी हो सकेगा, करेंगे। वे यहां जो सीखेंगे उसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे।

अमेरिका को लाभ मिलेगा : सांसद माइक क्विगले ने कहा कि विश्व के आर्थिक बाजार में टिके रहने के लिए अमेरिका को इसे बदलना होगा। अगर हम विदेशी छात्रों को अमेरिका से बाहर करेंगे तो अपने देश में तकनीक का विकास और नई खोज नहीं कर पाएंगे।